

प्रेषक,

सौरभ जैन  
अपर सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी  
उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 11-अगस्त, 2009

विषय- वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-515/xxvII(1)/2009 दिनांक 28.7.09 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों में जनपदवार जिला सेक्टर में रु0 60951-00 हजार (छ: करोड़ नौ लाख इक्कावन हजार मात्र) की धनराशि (शासनादेश संख्या 832/1/2008-03(1)/21/08 दिनांक 2-6-2009 के द्वारा पूर्व में स्वीकृत रु0 20320 हजार की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुरक्षण समितियों द्वारा अनुमोदित योजनावार एवं प्लान परिचय के अनुसार ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
- 2- व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनैन्सियल हैंडबुक, स्टोर पर्यज मूल्य मितव्ययता टैण्डर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण जिलाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को दिनांक 31.3.2010 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 4- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजनाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 5- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं पर केन्द्रांश एवं राज्यांश अवमुक्त किये जाने के बाद ही कोषागार से आवश्यक धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
- 7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
- 8- जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी



के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा।

9- जिलाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्तर-1 में वर्णित शासनादेश दिनांक 28.7.2009 में निहित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

10- ₹0 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति सम्बन्धित मण्डलायुक्त से सहमति प्राप्त कर जारी की जायेगी।

11- नये कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।

12- सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर वी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैन्युअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और यदि नियमित रूप से शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्यमंत्री जी/मुख्य सचिव) अर्थात् सक्षम स्तर को कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया जायेगा।

13- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2810-वैकल्पिक ऊर्जा-आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामों डाला जायेगा।

संलग्न:-यथोक्त।

भवदीय,

(सौरभ जैन)

अपर सचिव।

संख्या-1238 / 1/2008-03(1)/9/09 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
- 2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखंड।
- 3- निदेशक, उरेडा, देहरादून।
- 4- अधिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 5- नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-2
- 6- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- विभागीय आदेश मुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0सेमवाल)

अनु सचिव।



